यू.पी. राज्य

बनाम

मुंशी

(आपराधिक अपील संख्या 287/2007)

28 अगस्त, 2008

(डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा न्यायाधीपति)

दंड संहिता 1860 उपधारा 363, 366, 376:

बलात्कार, दोषसिद्ध, आरोपी को उच्च् न्यायालय ने इस आधार पर बरी किया कि अभियोजक एक सहमति देने वाला पक्ष था। अभियुक्त द्वारा बलात्कार किये जाने के समर्थन में अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं। अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय न्यायालय अपने कार्य/न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग निर्णय में कारण के बिना नहीं कर सकता- उच्च न्यायालय के फैसले को कारणों की अनुपस्थिति के कारण फैसले को टिकाउ नहीं ठहराया- इसके अलावा, अभियोजक पहले यौन संभोग की आदि है। यौन संभोग के लिए खुद को प्रस्तुत करने से इंकार करने के लिए उसे एक अधिकार है। उसकी गवाही की पुष्टि के बिना उपलब्ध सामगी एवं विवरण के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है। उच्च न्यायालय को मामले की पुनः सुनवाई का निर्देश दिया।

विचारण न्यायालय ने आरोपी-प्रतिवादीयों को धारा 363, 366 और 376 भा.द.सं. में दण्डनीय बलात्कार के आरोप का दोषी पाया। उच्च

न्यायालय ने आरोपियों को इस आधार पर दोषमुक्त किया कि अभियोजक एक सहमति देने वाला पक्ष रहा है और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपहरण और बलात्कार करने के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं। वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अपीलार्थी/राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को निर्णय में कारण दर्ज करना आवश्यक है। विशेष रूप से जब साक्ष्य के विश्लेषण और विस्तरित तरीके से विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है।

अपील की अनुमति दी गई। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः-

1.1 कारण एक क्रम में स्पष्ट प्रकट हो। न्याय पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को अपने कारण चाहे वे कितने भी संक्षिप्त हो न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करने का संकेत देते हैं और ये तब जब यह आदेश चुनौति के लिए उपयुक्त होता है। कारण की अनुपस्थिति के अभाव में उच्च न्यायालय का फैसला टिकाउ नहीं है। (पैरा-5)(901 बी-सी)

बरीन बनाम अमालगामेटेड इंजीनियर संघ (1971) 1 ऑल ईआर 1148 और अलेक्जेंडर मशीनरी (डूडली) लि. बनाम क्रेबट्री (1974) आईसीआर 120 (एनआईआरसी) संदर्भित।

1.2 कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारण लिखित करने पर प्रकाश डालते हुए यदि निर्णय "स्फिकस के अस्पष्ट चेहरे को प्रकट करता है, न्यायालयों के लिए इस संबंध में चुप

रहना अपने अपीलिय कार्य को पूरा करना या अपने अपीलीय शक्ति का प्रयोग करने को लगभग असंभव बना देता है। निर्णय की वैद्यता का निर्णय लेने में न्यायिक समीक्षा (पैरा-6) [901-ई, एफ]

1.3 तर्क का आधार ठोस न्यायिक प्रणाली का यह एक अनिवार्य हिस्सा है। न्यायालय के समक्ष मामले में कारण मस्तिष्क के प्रयोग के स्पष्ट संकेत हैं।

2.1 इसके अलावा यह तर्क की प्रभावित पक्ष को तत्काल मामले में यह पता चल सकता है कि साक्ष्य के अलावा उच्च न्यायालय ने कोई उसके विरूद्ध निर्णय क्यों दिया। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत के अनुसार आदेश में कारण होना आवश्यक है। (पैरा-7) [901-एच 902-ए]

2.2 यहां यह निर्धारक प्रश्न नहीं है कि पिड़ित पहले यौन संभोग की आदि थी। इसके विपरीत यह सवाल जिसको न्याय निर्णित करने की आवश्यकता थी कि क्या अभियुक्त ने पिड़िता के साथ बलात्कार किया। यह काल्पनिक रूप से स्वीकार किया गया हो कि पिड़िता ने पहले अपना कोमार्य खो दिया। इस कारण उसने किसी भी व्यक्त को उसके साथ बलात्कार करने का लाईसेंस नहीं दिया और न ही वह ऐसा दे सकती है। पिड़िता भले ही किसी मामले में यौन संबंध में स्वेच्छा से संलिप्त रही हो, उसे बाद में अभियुक्त के साथ और अन्य किसी के साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार है। क्योंकि वह किसी और के द्वारा या सभी के द्वारा बलात्कार करने का शिकार नहीं है। (पैरा-8) [902 ए, बी, सी]

2.3 यह तय किया गया कि बलात्कार के अपराध का शिकार होना और अभियोजक द्वारा शिकायत करना अपराध नहीं है। अपराध के बाद उसके बयान पर महत्वपूर्ण विवरण की पुष्टि के बिना कार्यवाही नहीं करने के संबंध में विधि का कोई नियम नहीं है। घायल गवाह अभियुक्त की तुलना में एक उंचे आसन्न पर खड़ी है। यदि न्यायालय प्रारंभ से ही अभियोजक के पक्ष को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है तो इस संबंध में उसे प्रत्यक्ष या परिस्थितजन्य साक्ष्य देखनी चाहिए। जिससे उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि होती है। (पैरा-9) [902-डी, ई, एफ]

2.4 उच्च न्यायालय को मामले को पुनः सुनना चाहिए और अपील को तर्क पूर्ण निर्णय द्वारा निपटारा करे। (पैरा-10)

3- यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई। (पैरा-10)

केस कानून संदर्भ

(1971) 1 ऑल ईआर 1148 संदर्भ पैरा-6

(1974) आईसीआर 120 (एनआईआरसी) संदर्भ पैरा-6

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार- आपराधिक अपील संख्या 287/2007।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनउ पीठ के क्रिमिनल अपील संख्या 317, 327/1987 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.03.2007 से उत्पन्न।

आर. दास, अनवृत शर्मा, फुजैल खां, सहदेव सिंह और अल्का सिन्हा अपीलार्थी पक्ष के लिए।

साकेश कुमार-प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय **अरिजीत पसायत, जे.** द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में चुनौती यूपी राज्य द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए दी गई है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरदोई ने 1985 के सत्र परीक्षण संख्या 455 में दोनों उत्तरदाताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 363, 366 और 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और बरी करने का निर्देश दिया।

2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय का आदेश, कम से कम, न केवल गूढ़ है बल्कि गैर-तर्कसंगत भी है। बरी करने का निर्देश देने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय ने केवल इस प्रकार टिप्पणी की:

> "मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है और मैंने रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने मेरा ध्यान रिकॉर्ड पर मौजूद चिकित्सीय साक्ष्य की ओर आकर्षित किया है, जिससे पता चलता है कि जिस

लड़की की बात की जा रही है उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष थी। इस प्रकार वह 19 वर्ष की भी हो सकती है। उसके शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई और वह संभोग की आदी थी। इस प्रकार, विचाराधीन लड़की बालिग प्रतीत होती है और इस प्रकार वह सहमति देने वाली पक्षकार थी और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया था या उसके साथ बलात्कार किया गया था। संबंधित लड़की उसी दिन सकुशल घर लौट आई। इस प्रकार निचली अदालत का अभियोजन सिद्धांत पर विश्वास करना और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना उचित नहीं था।"

3. अपीलकर्ता-राज्य के विद्वान वकील ने कारणों को दर्ज करने की वांछनीयता पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से, जब किए गए साक्ष्यों का विश्लेषण और विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत तरीके से निकाले गए निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा परेशान करने की मांग की जाती है।

4. दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि हालांकि विस्तृत कारण नहीं दिए गए हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को गलत पाया है।

5. कारण किसी क्रम में स्पष्टता लाते हैं। न्याय के स्पष्ट विचार पर, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न

हो, अपने दिमाग के प्रयोग का संकेत देते हुए, अपने कारण सामने रखने चाहिए थे, खासकर तब जब उसका आदेश चुनौती के आगे के अवसर के लिए उत्तरदायी हो। उच्च न्यायालय के फैसले को कारणों की अनुपस्थिति ने टिकाऊ नहीं बनाया है।

6. प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी लॉर्ड डेनिंग, एमआर ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971) 1 ऑल ईआर 1148, में कहा: "कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है।" अलेक्जेंडर में मशीनरी (डूडली) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री 1974 आईसीऔर 120 (एनआईआरसी) में यह देखा गया: "कारण बताने में विफलता न्याय से इनकार करने के समान है।" "कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और लिए गए निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत संबंध हैं।" कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर यह है कि यदि निर्णय "स्फिंक्स के गूढ चेहरे" को उजागर करता है, तो यह अपनी चुप्पी से, अदालतों के लिए अपने अपीलीय कार्य करना या वैधता तय करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना लगभग असंभव बना सकता है। फैसले का तर्क का अधिकार एक सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है; कारण कम से कम अदालत के समक्ष मामले पर दिमाग लगाने का संकेत देने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में

से एक दिए गए आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है; दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का गूढ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

7. मौजूदा मामले में, सबूतों की चर्चा तो दूर, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों से हटने का कोई आधार भी नहीं बताया है।

8. यह मान भी लिया जाए कि पीड़िता पहले से संभोग की आदी थी, तो भी यह कोई निर्णायक प्रश्न नहीं है। इसके विपरीत, जिस प्रश्न पर फैसला सुनाया जाना आवश्यक था वह यह था कि क्या आरोपी ने शिकायत के अवसर पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। भले ही यह काल्पनिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए कि पीड़िता ने पहले अपना कौमार्य खो दिया था, लेकिन यह कानून किसी भी व्यक्ति को उसके साथ बलात्कार करने का लाइसेंस नहीं दे सकता है और न ही देता है। मुकदमा चल रहा है वह व्यक्ति आरोपी है पीड़िता नहीं। भले ही किसी दिए गए मामले में पीड़िता पहले अपने यौन व्यवहार में स्वच्छंद रही हो, उसे खुद को किसी और तथा अन्य सभी के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने का अधिकार है क्योंकि वह किसी और तथा अन्य सभी के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार होने के लिए एक कमजोर वस्तु या शिकार नहीं है।

9. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बलात्कार के अपराध का शिकार होने की शिकायत करने वाली पीड़िता अपराध के बाद सहयोगी नहीं है। कानून का कोई नियम नहीं है कि उसकी गवाही पर भौतिक विवरण की

पुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह घायल एक गवाह से भी ऊंचे पायदान पर खड़ी है। बाद वाले मामले में, शारीरिक चोट लगती है, जबकि पहले मामले में यह शारीरिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होता है। हालाँकि, यदि तथ्यों की अदालत को अभियोजक के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसकी गवाही की पुष्टि करेगा।

10. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को मामले की दोबारा सुनवाई करनी चाहिए और तर्कसंगत निर्णय द्वारा अपील का निपटारा करना चाहिए। इसलिए, हम विवादित फैसले को रद्द करते हैं और मामले को नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय में भेजते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

11. अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस अपील स्वीकृत है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **लिलु राम सिहाग (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।